Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 01-03-2007
Participants : Chairman ,Bhargav Shri Girdhari Lal

Title: Need to take steps to contain rise in prices of essential commodities in the Country.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, आज देश को महंगाई मार गई है। महंगाई के साथ-साथ ओले भी मार गए। इससे दोहरी मार देश की जनता पर पड़ी है। आज आटा, दाल और चावल के दाम बहुत बढ़ गए है। तेल और गैस लोगों को मिल नहीं रही है। उसकी एक-दो महीने की बुकिंग है। उन्हें समय पर गैस और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पा रहा है। पैट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से सब्जियां महंगी हो गईं हैं। लकड़ियां जिन से दाह संस्कार किया जाता है, वे भी महंगी हो गईं हैं। आज यह स्थिति हो गई है कि कमाओ तो टैक्स, जोड़ो तो टैक्स और मर जाओ तो टैक्स। लाश भी उस समय उठेगी जब टैक्स चुका दिया जाएगा। कमाओ, जोड़ो और मर जाओ। इन सब चीजों पर टैक्स देना पड़ता है। आज देश की जनता महंगाई और ओलावृटि से बहुत दुखी है। संसदीय कार्य मंत्री मेरे सामने विराजमान हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वह एक स्पैशन चर्चा महंगाई और ओलावृटि पर करवाएं। जो चीजें आसानी से नहीं मिल रही हैं, वे उपलब्ध करानी चाहिए। जिन चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, केन्द्र सरकार को उन पर रोक लगानी चाहिए। जनता ने इनका दो जगह पर असर दिखा दिया है। वह आगे यूपी वगैरह दूसरे राज्यों में भी दिखाने वाली है। सरकार इस बारे में सचेत हो जाए। ओलावृटि के कारण भगवान की कुदृटि पड़ रही है। हम महंगाई को रोकें। मुझे विश्वास है कि मेरी बात पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी और एक दिन महंगाई और ओलावृटि पर चर्चा करवाएगी।

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the Minister of Human Resource Development the issue of non-observance of rules of reservation in National Institutes of Technology (NITs). As you are aware, the NITs were converted from Regional Engineering Colleges (RECs) under Section 3 of the UGC Act, 1956. All major States were having these RECs under the Central and State Government schemes. After they were converted into NITs, these institutions are not observing the rules of reservation in recruitments and promotions. These rules were observed when they were RECs and the people from SCs, STs and OBCs were recruited as Professors, Lecturers and Assistant Professors.

MR. CHAIRMAN : That issue is still pending before the Supreme Court and the Government is pursuing it very vigorously.